PR PROFESSIONALS
Race for Excellence

Publication	Punjab Kesari
Language/Frequency	Hindi/Daily
Page No	II
Date	19th Jan 2019

पंजाब केसरी

केंद्र के नए बजट से कारोबारियों को आस, आवास होंगे सस्ते

गुड़गांव, 17 जनवरी (ब्यूरो): लोकसभा चुनावों के दरवाजे पर खड़ी सरकार से कारोबार जगत ने उम्मीद लगा रखी है, खासकर आवास कारोबारी जीएसटी में छूट सहित आधारभूत ढांचे सहित बैंकिंग में सुधार की उम्मीद लगाए हैं।

देश के सबसे बड़े रियल एस्टेट हब गुड़गांव में तकरीबन दस हजार आवास बिकने को तैयार है, तो सैकड़ो प्रोजेक्ट निर्माणाधीन है। सरकार ने लचीला रुख अपनाया तो साल 2019 आवास के नजरिये से नई छलांग साबित होगा। हालांकि नोटबन्दी के बाद से इस क्षेत्र को बड़े नीतिगत परिवर्तनों की आस है ताकि कारोबार पटरी पर आ सके इसके लिए करोबार जगत तैयार है। माल और सेवा कर की दर में कमी ने घर खरीदारो की

मांग बढ़ा दी है। एनसीआर में आवास और बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई भूमि पूभलग नीति से दिल्ली में हजारों घर खरीदारों के सपनों को पूरा करने की उम्मीद है। तो वहीं सरकार की

गुड़गांव के लिए अहम साबित होगा 2019

गुड़गांव में तेजी से विकसित हुए एक्सप्रेस-वे, फ्लाईओवर, सड़कों, पुलों के खुलने के साथ और दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचने वाले मेट्रो नेटवर्क के विस्तार के कारण साल 2019 अहम साबित होने जा रहा है। आवागमन के कई विकल्पों के खुलने के साथ ही रैपिड रेल और हाईस्पीड रेल की शुरुआत गुड़गांव में रियल एस्टेट के लिए वरदान साबित होगा। इन क्षेत्रों में रहने और काम करने के लिए जनता जहां से वे दैनिक आधार पर आसानी से आवागमन कर सकते हैं।

इस नीति से गुड़गांव में कई परिवर्तन देखे जा सकते हैं जिसका लाभ खरीददारों को ही मिलेगा।

कारोबारी कहते हैं कि बुनियादी आवश्यकताओं में आवास आम लोगों की जरूरत है जिसे सक्रिय सार्वजनिक नीति के दायरे से बाहर छोड़ दिया गया है। आवास क्षेत्र को अभी भी आधारिक संरचनात्मक स्थिति का इंतजार है और इसने निवेश को इससे दूर रखा है। जबकि होम लोन और भवन की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, नियामक तंत्र गति के साथ बनाए रखने में विफल रहा है, जिसके कारण लागत मूल्य में बढोत्तरी हुई है। कारोबारियों की ओर से पेश की जाने वाली बहुपक्षीय योजनाओं और छूट से खरीदार आकर्षित होते रहे हैं। हांलाकि किफायती आवास की स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है। इसके अलावा बिल्डर्स जो प्रधानमंत्री आवास योजना और दीनदयाल आवास योजना में शामिल हैं, उन्होंने भी भविष्यवाणी की है कि 2019 में दाम घटेंगे। 2018 में रियल एस्टेट में मजबूत वापसी के पिछले दावे दुर्भाग्य से सही साबित नहीं हुए।

किफायती आवास

सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में सबके लिए आवास पहली प्राथमिकता है इस साल को भी किफायती आवासो के लिए अहम साल माना जा रहा है। सरकार की मंशा के अनुरुप साल 2019 में अफोर्डेबल हाउभसग के रूप में रूझान में तेजी आएगी। सस्ते घरों की मांग सबसे अधिक है और अपने नाम के अनुसार ये खरीददारो के बड़े वर्ग के लिए भी आसान होगा।

"माल और सेवाकर की दर में कमी ने खरीददारों की मांग को बढ़ा दिया है, सरकार को चाहिए कि देश के जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देने वाले इस क्षेत्र में बैंकिंग नियमों को और सरल करें। *नेह श्रीवास्तव, अध्यक्ष, सेंट्रल सेक्रेटरीयाट सर्विसेज ऑफिसर सोसायटी*

"हमारी उम्मीद है कि आयकर में छूट, सिंगल विंडो सहित सड़क परियोजनाओं में सरकार निवेश बढाएगी जिससे इस क्षेत्र में और तेजी की उम्मीद की जा सकती है। *आशीष सरीन निदेशक अल्फाकार्प*

Corporate Office: 212, 2nd Floor, JMD Regent Plaza, DLF Phase-1, Gurugram, Haryana-122001
• Mumbai • Bangalore • Hyderabad • Lucknow • Chandigarh • Noida • Kolkata • Jaipur • Patna